NEERAJ®

भारतीय अर्थव्यवस्था-II

(Indian Economy-II)

B.E.C.E.-146

B.A. General - 6th Semester

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Harmeet Kaur

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

भारतीय अर्थव्यवस्था–II

(Indian Economy-II)

Question Paper–June-2023 (Solved)..... 1-2

Question Paper–December-2022 (Solved)..... 1-2

Question Paper Exam Held in July 2022 (Solved)..... 1-3

Sample Question Paper–1 (Solved) 1-2

Sample Question Paper–2 (Solved) 1-2

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

समष्टि आर्थिक नीतियाँ

(Macroeconomic Policies)

1. मौद्रिक नीति 1
   (Monetary Policy)

2. राजकोषीय नीतियाँ 17
   (Fiscal Policy)

3. व्यापार और निवेश नीति 29
   (Trade and Investment Policy)

4. श्रम कानून एवं विनियमन 41
   (Labour Laws and Regulations)

कृषि क्षेत्र

(Agricultural Sector)

5. कृषि क्षेत्र का निष्पादन 55
   (Performance of Agricultural Sector)

6. कृषिक संबंध एवं बाजार सहलग्नताएँ 65
(Agrarian Relations and Market Linkages)

7. पूँजी निर्माण एवं उत्पादकता 78
(Capital Formation and Productivity)

8. कृषि नीति 89
(Agricultural Policy)

औद्योगिक क्षेत्र
(Industrial Sector)

9. औद्योगिक नीति और संवृद्धि 101
(Industrial Growth and Policy)

10. छोटे पैमाने के उद्योग 114
(Small Scale Industries)

सेवा क्षेत्र
(Service Sector)

11. सेवा क्षेत्र की विशेषताएँ 127
(Features of Service Sector)

12. सेवा क्षेत्र के नीतिगत मुद्दे 138
(Policy Issues for Service Sector)

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

भारतीय अर्थव्यवस्था–II

B.E.C.E.-146

(Indian Economy-II)

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *प्रत्येक भाग में प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए।*

भाग-क

नोट : इस भाग से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1. विभिन्न देशों द्वारा अपने व्यापार हितों को बढ़ावा देने के लिए अपनाए जाने वाले 'क्षेत्रवाद' के संदर्भ में 'द्विपक्षीयता' और 'बहुपक्षवाद' के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-38, प्रश्न 15, प्रश्न 16

प्रश्न 2. प्रारंभिक आर्थिक विचारकों द्वारा 'कृषि क्षेत्र' को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से अंतर्सम्बन्ध की परिकल्पना कैसे की गई थी? व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-55, 'परिचय', पृष्ठ-60, प्रश्न 7

प्रश्न 3. भारत में 'सेवा क्षेत्र' को प्रभावित करने वाली हाल की एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहल क्या है? भारत में सेवा क्षेत्र के विस्तार की संभावनाओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-12, पृष्ठ-140, प्रश्न 1, पृष्ठ-142, प्रश्न 5

प्रश्न 4. लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के सैद्धांतिक महत्त्व की व्याख्या कीजिए। नई औद्योगिक नीति (NIP), 2017, में SSI क्षेत्र के लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-10, पृष्ठ-114, 'लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु तर्काधार', पृष्ठ-123, प्रश्न 14

भाग-ख

नोट : इस भाग से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 5. एक अर्थव्यवस्था के मौद्रिक आधार से क्या तात्पर्य है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-4, प्रश्न 2

प्रश्न 6. राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या हैं? एक राजकोषीय नीति के कुछ महत्त्वपूर्ण आर्थिक निहितार्थों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-19, प्रश्न 1, पृष्ठ-20, प्रश्न 3

प्रश्न 7. कौन-सा सामाजिक सुरक्षा कानून छोटे सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को कवर करता है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-48, प्रश्न 10

प्रश्न 8. भारत की काश्तकारी अवस्था का विश्लेषण कीजिए। विलोम काश्तकारी क्या है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-66, 'काश्तकारी व्यवस्था', पृष्ठ-71, प्रश्न 9

प्रश्न 9. किसान उत्पादक संगठन किस प्रकार भारत में 'छोटे किसान समूह' की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण सुधार है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-8, पृष्ठ-97, प्रश्न 11

भाग-ग

नोट : इस भाग में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन में अंतर स्पष्ट कीजिए–

(क) वस्तु बाजार और कारक बाजार

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-67, 'वस्तु एवं कारक बाजार'

इसे भी देखें–कृषि उत्पादन एवं निवेशों के आधार पर, बाजार दो श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं–माल बाजार और कारक बाजार। वस्तु अथवा माल बाजार ऐसे पण्यक्षेत्र हैं, जहां कृषि उत्पाद बेचे और खरीदे जाते हैं, जबकि कारक बाजारों में, फार्म आदानों का व्यापार किया जाता है। किसानों को खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार की आदानों की आवश्यकता होती है, जैसे–बीमा, रासायनिक, उर्वरक, कीटनाशी, कृषि-यंत्र, श्रमिक व अन्य सेवाएं। कृषि को एक लाभकारी उद्यम बनाने के लिए उक्त बाजारों का किसानों के साथ प्रभावपूर्ण सहलग्नता अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए, विधि-अनुकूल ऋण बाजार के किसानों की प्रभावपूर्ण सहलग्नता के अभाव में वे गैर-कानूनी कर्ज बाजार से लिए गए अपने ऋणों पर ब्याज की बेहद ऊँची दर चुकाने को बाध्य हो जाते हैं। किसानों के बीच ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारणों में एक उन्हें प्राप्त विधि-अनुकूल ऋण का अभाव भी है। इसी प्रकार, कृषि माल-बाजारों का नियंत्रण अनेक बिचौलियों द्वारा किया जाता है, जो कृषि जिंसों के लिए किसानों को मिलने वाले दाम और उपभोक्ताओं द्वार चुकाए गए दाम के बीच बनावटी रूप से बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं।

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

(ख) वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र

उत्तर–मुद्रा की नाममात्र मांग का अर्थ है–किसी व्यक्ति द्वारा मांग की गई मुद्रा की मात्रा (उदाहरण के लिए भारत में रुपये की संख्या)। मुद्रा की वास्तविक मांग भी मुद्रा की मांग है, लेकिन उस वस्तु की इकाइयों की संख्या के संदर्भ में जिसको मुद्रा से खरीदा जा सकता है। मुद्रा की वास्तविक मांग को नाममात्र की मुद्रा को कीमत स्तर द्वारा विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मुद्रा की नाममात्र मांग (जिसे नाममात्र की सम्पत्ति, nominal wealth-WN भी कहा जाता है) 500 रुपये है, और कीमत स्तर 5 रुपये है। फिर मुद्रा की वास्तविक मांग वस्तुओं की 100 इकाइयों (= 500/5) के बराबर होगी।

यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि अगर मुद्रा की नाममात्र मांग और कीमत स्तर दोगुना हो जाता है, तो मुद्रा की वास्तविक मांग अपरिवर्तित रहती है। मुद्रा की वास्तविक मांग को 'वास्तविक मुद्रा शेष की मांग' या वास्तविक शेष राशि के रूप में भी जाना जाता है। ऋण पत्र के वास्तविक धारण को मुद्रा और ऋण पत्र धारण के योग को कीमत स्तर से विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की वास्तविक वित्तीय संपत्ति, वास्तविक शेष राशि (real balances - L) और वास्तविक ऋण पत्र स्वामित्व (bond holdings-BH) की मांग के योग के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा वास्तविक वित्तीय संपदा को देखने का एक और तरीका कीमत स्तर (P) द्वारा नाममात्र की मुद्रा (WN) का विभाजन है, इसलिए,

$$L + BH = \frac{WN}{P}$$

अधिक वास्तविक शेष रखने के निर्णय का अर्थ है–ऋण पत्र के रूप में कम वास्तविक संपदा रखने का निर्णय। अगर हम केवल मुद्रा बाजार पर विचार करते हैं, तो हम परिसंपदा बाजार को समझ सकते हैं। यदि मुद्रा बाजार संतुलन में है, तो बॉन्ड बाजार भी संतुलन में होगा, क्योंकि वास्तविक मुद्रा इन दो बाजारों में ही की जाती है।

किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर उपलब्ध वास्तविक वित्तीय धन, वास्तविक नगद शेष राशि और उपलब्ध वास्तविक ऋण पत्रों का योग होगा।

(ग) क्षेत्रवाद और बहुपक्षवाद

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-31, 'क्षेत्रवाद, द्विपक्षवाद और बहुपक्षवाद'

(घ) चालू खाता परिवर्तनीयता और पूंजी खाता परिवर्तनीयता

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-34, प्रश्न 6

प्रश्न 11. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर लघु टिप्पणियां कीजिए–

(क) भारत का प्रतियोगिता आयोग

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-104, 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग'

(ख) वस्तु एवं सेवा कर (GST)

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-12, पृष्ठ-139, 'वस्तु एवं सेवा कर (GST)' तथा पृष्ठ-148, प्रश्न 4, '*(i)* वस्तु एवं सेवा कर'

(ग) श्रमिकों का प्रवास

उत्तर–एक 'प्रवासी श्रमिक' वह व्यक्ति होता है, जो या तो अपने देश के भीतर या इसके बाहर काम करने के लिए पलायन करता है। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं, जिसमें वे काम करते हैं।

अपने देश के बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को विदेशी श्रमिक भी कहा जाता है। उन्हें प्रवासी या अतिथि कार्यकर्ता भी कहा जा सकता है, खासकर जब उन्हें स्वदेश छोड़ने से पहले मेजबान देश में काम करने के लिए भेजा या आमंत्रित किया गया हो।

2014 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान था कि दुनिया भर में 232 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे, जो कम से कम 12 महीनों के लिए अपने गृह देश से बाहर थे और उनमें से लगभग आधे आर्थिक रूप से सक्रिय होने का अनुमान लगाया गया था।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि (और विधि प्रावधान) अधिनियम (EPFA), 1952

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-42, 'कर्मचारी भविष्य निधि (और विभिन्न प्रावधान) अधिनियम, 1952', पृष्ठ-47, प्रश्न 9

(ङ) व्यापार और सेवाओं पर सामान्य समझौता (GATS)

उत्तर–1947 में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) कोटा, टैरिफ और सब्सिडी को समाप्त या कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने वाली एवं संधि है। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना था।

पिछले कुछ वर्षों में GATT का विस्तार और परिष्करण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1995 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) का निर्माण हुआ, जिसने GATT को लागू करने के लिए बनाए गए संगठन को समाहित कर लिया। तब तक 125 राष्ट्र इसके समझौतों पर हस्ताक्षरकर्ता थे, जो वैश्विक व्यापार का लगभग 90% कवर करते थे।

माल व्यापार परिषद (माल परिषद) अब GATT के लिए जिम्मेदार है और इसमें सभी WTO सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सितंबर 2022 तक गुड्स काउंसिल के अध्यक्ष एटिने औडोट डी डेनविले थे। परिषद में 10 समितियां हैं, जो बाजार पहुँच, कृषि सब्सिडी और डंपिंग रोधी उपायों सहित विषयों को संबोधित करती हैं।

इसे भी देखें–संदर्भ–अध्याय-12, पृष्ठ-144, प्रश्न 9

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

भारतीय अर्थव्यवस्था-II
(Indian Economic-II)

समष्टि आर्थिक नीतियाँ
(Macroeconomic Policies)

मौद्रिक नीति
(Monetary Policy)

1

परिचय

मौद्रिक नीति के व्यापक उद्देश्य हैं। मौद्रिक नीति का प्रबंधन देश का रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक बैंकों के तीन बुनियादी समष्टि अर्थशास्त्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जैसे कि आर्थिक विस्तार के लिए मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, उत्पाद बढ़ाना तथा कीमत स्थिर करना, रुपये के अधिमूल्यन और अवमूल्यन से स्थिरता देना। आर्थिक संवृद्धि को गतिशील बनाने के लिए और स्थिरता लाने के लिए तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक उपभोग और निवेश के कई स्तरों द्वारा कुल माँग के स्तर को उठाने में सहायक होता है। मुद्रा की आपूर्ति के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे कि आरक्षित मुद्रा और विदेशी पूँजी प्रवाह। रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कई नीति उपकरणों द्वारा नियंत्रित करता है। लगभग 2000 से 2005 के दौरान भारत में मौद्रिक नीति क्रिया-विधि से काफी परिवर्तन हुए।

अध्याय का विहंगावलोकन

मुद्रा की आपूर्ति के स्रोत

नकद मुद्रा और जमा मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था से मुद्रा की आपूर्ति के दो स्रोत हैं। केंद्रीय बैंक में मुद्रा की आपूर्ति का आधार तरलता है, यानी हाथ में मुद्रा तरल होती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं से विनिमय में बड़ी आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। अवरोही क्रम में तरलता की चार श्रेणियाँ हैं–M_1, M_2, M_3, M_4, जैसे कि $M_1 = C + DD + DD$ होती है, यानी इसमें मुद्रा का कैश रूप, व्यापारिक माँग, जमा राशि और अन्य वित्तीय संस्थानों की राशि शामिल है। सर्वाधिक तरलता के कारण इसे M_4 की अपेक्षा संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, जबकि M_4 व्यापक मुद्रा मानी गई है। इसी प्रकार में M_2 में M_1 और डाकघरों की जमा राशियां भी शामिल होती हैं। M_3 में M_1 और M_2 की जमा राशि होती है, जबकि M_4 में डाकघरों की बचत राशियां और M_3 शामिल की जाती है।

आरक्षित मुद्रा

मुद्रा की आपूर्ति का दूसरा स्रोत सृजित मुद्रा माना गया है। यह लोगों को दिया गया ऋण है, जो कि नकद आरक्षित अनुपात बैंकों के पास लोगों की जमा कराई गई नकद और माँग जमा राशि के रूप में बैंकों के पास आरक्षित होती है। यह जमा गुणक के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने पास जमा राशियों में अन्य साख मुद्रा का निर्माण कर सकते हैं। नकद आरक्षित अनुपात और विलोमत संबद्ध होते हैं। M_1 को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। यह उच्च शक्तिशाली मुद्रा द्वारा साख सृजन बैंकिंग प्रणाली की क्षमता को प्रभावित करता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कुल जमा राशियों का आकार तीन कारकों–उच्च शक्ति की मुद्रा, नकद आरक्षित अनुपात और कुल बैंक जमा राशियों के अंश पर निर्भर करता है।

विदेशी पूँजी प्रवाह

विदेशी पूँजी प्रवाह मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करता है, जैसे कि भारत में जब विदेशी पूँजी आती है, तो रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में वृद्धि होती है, यानी रिजर्व बैंक रुपए के अधिमूल्यन को रोकने के लिए पूँजी अंतर्वाहों को रुपये के पदों में परिवर्तित करता है, जिससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। अगर पूँजी का प्रवाह विदेश में होता है, तो रुपये के अवमूल्यन को रोकने के लिए रिजर्व बैंक रुपये को डॉलरों में विनिमय करता है। इसी प्रकार जब कोई विदेशी भारत में पूँजी या

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

वस्तु का आगमन करता है, तो उसे भुगतान रुपये में ही किया जाता है, यानी रिजर्व बैंक में उस मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदल दिया जाता है।

मौद्रिक नीति के उपस्कर

प्रत्येक बैंकिंग व्यवस्था और मुद्रा बाजार को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है, इसलिए वह बैंकों की ऋण सृजन क्षमता घटाने के लिए परिमाणात्मक उपाय और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की दिशा में ऋण प्रवाह के लिए गुणात्मक उपाय करता है। रिजर्व बैंक की भूमिका में 1980 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने नया आयाम जोड़ा कि रिजर्व बैंक को भारतीय मुद्रा बाजार के विकास हेतु नई मौद्रिक और वित्तीय संस्थानों के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए। रिजर्व बैंक विभिन्न नीति उपस्करों द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रित करता है। यह मौद्रिक नीति का प्राधार तथा आवधिक रूप में उसका मूल्यांकन करता है, जैसे कि संचलन में रोकड़ का नियंत्रण और साखमुद्रा को नियंत्रित करना। यह मुद्रा की वर्तमान माँग को पूरा करने के लिए नई मुद्रा जारी करता है। पूर्ववर्ती की अपेक्षा परवर्ती हेतु बैंक दर, नकदी आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात और मुक्त बाजार संक्रियाओं जैसे नीति उपाय करता है। बैंक में मुद्रा की आपूर्ति हेतु अन्य उपायों में शामिल हैं–साखमुद्रा वितरण-नियंत्रण, चयनात्मक साखमुद्रा नियंत्रण, तरलता समंजन सुविधा और नैतिक प्रत्यापन।

आरक्षित अनुपात

नकद आरक्षित अनुपात संबंधी नियम प्रत्येक बैंक के लिए अनिवार्य होते हैं। नकद आरक्षित माँग नीति के अंतर्गत बैंक कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग तरल कैश के रूप में रखें और बाकी रिजर्व बैंक में जमा करा दें, यह अनुपात प्रत्यक्ष रूप से बैंकों को उधार देने की क्षमता को प्रभावित करता है। रिजर्व बैंक उन बैंकों पर दाण्डिक ब्याज दर लगता है, जो इन नियमों में असफल होते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपस्कर है। यह बैंकों के पास कैश व अन्य संसामुद्रों का कुछ भाग होता है, यानी नकद आरक्षित अनुपात प्राथमिक और वैधानिक तरलता अनुपात होता है। दूसरा आरक्षित माँग में शामिल होता है। नकद, सोना और अन्य सरकारी प्रत्याभूतियां, यह मुद्रा की तरलता को बनाए रखता है और बैंकिंग साख सृजन को नियंत्रण करने में सहायक है।

बैंक दर

बैंक दर विनिमय पत्रों और वचन पत्रों का रूप है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा होता है। यह बुनियादी रूप से ब्याज दरें हैं, जिन पर रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थानों को ऋण और मुद्रा प्रदान करने का दायित्व होता है, यानी यह उधार ली गई मुद्रा की लागत को पूरा करता है क्योंकि रिजर्व बैंक की बैंक दर बढ़ने से बैंक और वित्तीय संस्थान भी अपनी दरें बढ़ा देते हैं, जिससे मुद्रा और ऋण की माँग सीमित होती है।

रेपो एवं रिवर्स रेपो दरें

भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को मुद्रा की कमी को पूरा करने हेतु उधार के रूप में देता है। यह रेपो दर मुद्रास्फीति की अल्प अवधि को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। रेपो दर का अल्प रिवर्स रेपो दर है। यह वह दर है, जिस पर व्यापारिक बैंक अपनी मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। रिवर्स रेपो दर बढ़ाकर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी अतिरिक्त मुद्रा को साझा करने के लिए बढ़ावा देता है।

मुक्त बाजार संक्रियाओं द्वारा भी भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण करता है, यानी यह बैंक सरकारी प्रत्याभूतियों की खरीद-बेच करता है। इससे नकद आरक्षित मुद्रा में वृद्धि होती है और शाख सृजन क्षमता कम होती है। 1990 के दशक में रेपो द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया गया। साख का वितरण-नियंत्रण, ऋणों पर लाभ और नैतिक प्रत्यापन अन्य नीति उपस्कर हैं, जिनका उपयोग कर मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य

मौद्रिक प्रसार विधि द्वारा मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है। मुद्रा की आपूर्ति का प्रसार आर्थिक संवृद्धि में तीव्रता लाता है। ब्याज दरों द्वारा मौद्रिक स्रोत से वास्तविक क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। मौद्रिक प्रसार क्रियाविधि प्रसारकारी और संकुचनकारी उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे कि पूर्ववर्ती के लिए मुद्रा की माँग बढ़ाने से वाणिज्यिक बैंक प्रत्याभूतियों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक का रुख करते हैं। प्रत्याभूतियों के बदले में बैंक नई मुद्रा जारी करता है, इससे ब्याज दर घट जाती है और लोग निजी निवेश और उपभोग व्यय दरों को बढ़ाते हैं। लोग बचत करते हैं। इससे कुल अर्थव्यवस्था माँग में कमी होती है। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों को घटा या बढ़ा कर मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।

कीमत स्थिरता

कीमत में अस्थिरता होने से अर्थव्यवस्था जल्द ही उत्कर्ष और मंदी के रूप में विस्तारित होती है। इसलिए मौद्रिक नीति का उद्देश्य कीमतों में स्थिरता हेतु आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। मौद्रिक नीति क्रियाविधि इस अस्थिरता का सामना करने में सक्षम होनी चाहिए क्योंकि जहां उत्कर्ष आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा देता है, तो कीमतों में उछाल आता है। वहाँ मंदी आर्थिक गतिविधियों को कम करती है, तो कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक विशाल अनौपचारिक क्षेत्र, विशाल क्षेत्र और घरेलू माँग वित्त से विद्यमानता को मंदी कम प्रभावित करती है। यानी उत्पाद की कुल माँग बढ़ाने और कीमतों को स्थिर करने में प्रसारकारी राजकोषीय नीति सहायक होती है। एक सुदृढ़ मौद्रिक नीति जो कि संकुचनशील राजकोषीय नीति द्वारा प्रभावित हो, वह कुल माँग घटाकर कीमतें स्थिर करने और उत्कर्ष हेतु संभावना को बढ़ाती है।

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

विनिमय दर स्थिरता

विनिमय दर स्थिरता में अनुमानिक कार्रवाइयों द्वारा घरेलू मुद्रा में स्थिरता बनाई जाती है। इसके तहत विनिमय दर स्थिर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के उद्देश्यों के मध्य एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। एक अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। उन स्थानों में जहाँ ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति दुबारा पुनर्स्थापन हेतु अर्थव्यवस्था प्रभावित होती हो। जैसे कि समान कीमत के ऋणपत्र बेचकर पूँजी अंतर्वाहों से मुद्रा की आपूर्ति में संतुलन द्वारा विनिमय दर सीमित की जा सकती है। विदेशी पूँजी में अंतर्वाही मुद्रा का प्रवाह मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण करने में सहायक होता है।

आर्थिक संवृद्धि

ब्याज दर गिरने से निजी निवेश और उपभोग व्यय को बढ़ावा मिलता है, यानी सरल मौद्रिक नीति अपनाकर ब्याज दर को घटाकर माँग बढ़ाई जा सकती है, इससे अर्थव्यवस्था में तीव्रता आती है और नये वित्तीय संस्थानों का निर्माण हो सकता है।

निर्यात प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं समता

मौद्रिक नीति निर्यात और आयात को प्रोत्साहित और हतोत्साहित करने के लिए रुपया विनिमय दर को कम किया जा सकता है, यानी आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। निर्यातकों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिससे रोजगार स्तर को बढ़ावा मिल सकता है। अग्रता परिदाय नीति द्वारा आसान ऋणों से निर्धन वर्ग को सहायता मिल सकती है।

भारत में मौद्रिक नीति क्रियाविधि में परिवर्तन

भारत में मौद्रिक नीति में 1990 से 2005 के दौरान कई परिवर्तन आये। विश्व आर्थिक एकीकरण और बहु-बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पन्न नई वास्तविकताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए यह परिवर्तन हुए। इसमें कुछ दृष्टिकोण शामिल किए गए, जैसे कि मुक्त बाजार संक्रियाएं, तरलता समंजन सुविधा, बाजार स्थिरीकरण योजना और सीमांत स्थायी सुविधा की स्थापना।

तरलता समंजन सुविधा

2004 में संशोधित तरलता समंजन सुविधा योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 में शुरू की गई। इस योजना के तहत अल्पावधि तरलता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के रूप में दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति में इन दरों का मूल्यांकन करता रहा है। यह योजना मौद्रिक नीति में मुक्त बाजार संक्रियाओं और बैंक दर परिवर्तनों के संयोजन की प्रमुख तकनीक है।

बाजार स्थिरीकरण योजना

बाजार स्थिरीकरण योजना 2004 में शुरू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा की खरीद से उत्पन्न तरलता का निराकरण करना और विनिमय दर को बचाए रखना है। इसमें बाजार स्थिरीकरण के लिए बैंक द्वारा सरकारी ऋणपत्रों और प्रत्याभूतियों को बेचा जाता है।

सीमांत स्थायी सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा 2011 में विकसित की गई। इसमें बैंक मान्य सरकारी प्रत्याभूतियों के बदले भारतीय रिजर्व बैंक से एक रात के लिए मुद्रा उधार ले सकते हैं क्योंकि यह आकस्मिक देन है, इसलिए इसमें रेपो दर अधिक होती है। हालांकि यह आकस्मिक परिदाय दरों में उतार-चढ़ाव की स्थिति पैदा करता है, परंतु मुख्य उद्देश्य आकस्मिक अस्थिरता कम करना है।

भारत में 2015 में एक नया मौद्रिक नीति प्राधार शुरू किया है। इसमें संबद्ध मुद्रा स्फीति लक्ष्य निर्धारित किया गया। जैसे कि 2016 तक 6% और 2017-2018 के अंत तक 4% का एक उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सी.पी.आई.) किया गया। जबकि अखिल भारतीय मुद्रास्फीति 2014-2015 तक 5.9 रही और जून 2017 में 1.54 तक रही, यानी सीमांत स्थायी सुविधा में यह समझौता मुद्रा स्फीति दर को सीमित करने में सक्षम रहा।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. मौद्रिक नीति के प्रमुख समष्टि-अर्थशास्त्रीय उद्देश्य बताइए?

उत्तर–मौद्रिक नीति के अंतर्गत बहुविधि उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। यह प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मौजूद समग्र मौद्रिक प्रबंध मुद्रा है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख समष्टि-अर्थशास्त्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इससे वह देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति के प्रमुख समष्टि-अर्थशास्त्रीय उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. आर्थिक विस्तार के लिए वांछित मुद्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करना–मौद्रिक नीति का प्रमुख समष्टि-अर्थशास्त्रीय उद्देश्य आर्थिक विस्तार के लिए वांछित मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। इसमें आर्थिक विकास के लिए और आर्थिक विस्तार के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दर को घटाकर माँग को आसानी से बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ब्याज की दरों में गिरावट आने से प्रत्येक व्यक्ति निवेश की सोचता है या फिर उपभोग और व्यय को बढ़ावा मिलता है, जिससे माँग में वृद्धि होती है। इस प्रकार पूँजी निर्माण के साथ अर्थव्यवस्था तीव्र होती है और नई वित्तीय संस्थाओं का निर्माण कर मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे आर्थिक विस्तार होता है। इस प्रकार एक सरल मौद्रिक नीति का प्रयोग कर मुद्रा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

2. उत्पादन को बढ़ाने के साथ कीमत स्थिर करना–मौद्रिक नीति का दूसरा प्रमुख उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना है और कीमत को स्थिर रखना है। हालांकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में व्यापार में लाभ और हानि होते रहते हैं और ये दोनों बहुत जल्दी विस्तारित

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

भी हो जाते हैं इसलिए मौद्रिक नीति का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना है क्योंकि प्रत्याशाओं द्वारा कुल माँग बढ़ाने पर लाभ के समय आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों में तीव्रता आती है और उत्पादन बढ़ता है। मंदी के दौर में आर्थिक गतिविधियां कम होती हैं, जिससे घरेलू उत्पाद और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर कुल माँग का बढ़ना कीमतों में स्थिरता भी लाता है। ब्याज दरें घटाने से उपभोग-माँग और निवेश-माँग को बढ़ावा मिलता है और बचत को कम करने में मदद मिलती है। इस प्रकार माँग बढ़ाने से कीमतों में स्थिरता आती है।

3. रुपये के अधिमूल्यन और अवमूल्यन से बचाकर स्थिरता लाना–मौद्रिक नीति का तीसरा समष्टि-अर्थशास्त्रीय उद्देश्य रुपये के अधिमूल्यन और अवमूल्यन से बचाकर स्थिरता लाना है। रूपये के अधिमूल्यन को स्थिर रखने के लिए बैंक द्वारा अधिक घरेलू मुद्रा जारी की जाती है। इससे देयता पक्ष में वृद्धि होती है। इसी प्रकार रुपये के अवमूल्यन को स्थिर रखने के लिए देयताओं को बराबर करने के लिए रुपये को अक्षरों में विनिमय करता है, यानी दोनों कार्यों से मुद्रा की आपूर्ति को कायम रखने के लिए रुपये के अधिमूल्यन और अवमूल्यन को स्थिर रखा जाता है। इस प्रकार मौद्रिक नीति के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक उपभोग और निवेश के प्रत्येक स्तर द्वारा कुछ माँग का स्तर बढ़ाते हैं और आर्थिक संवृद्धि को गतिशीलता प्रदान करते हैं। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति का दायित्व रहता है।

प्रश्न 2. किसी अर्थव्यवस्था के 'मौद्रिक आधार' से क्या अर्थ लिया जाता है?

उत्तर–किसी अर्थव्यवस्था का 'मौद्रिक आधार' मुद्रा की आपूर्ति में विशेष महत्त्व रखता है। मुद्रा चाहे वह नकद हो या जमा दोनों रूपों में मुद्रा को व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि किसी परिसंपत्ति को उसकी तरलता के आधार पर नकदी मुद्रा में बड़ी सरलता और शीघ्रता से बदला जा सकता है। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं से विनिमय में यह मुद्रा यानी तरल मुद्रा सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है। किसी अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार लोगों के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा राशियां और चालू खाते तथा अन्य बैंक संस्थानों में जमा राशियां क्योंकि कैश मुद्रा सबसे ज्यादा तरल होती है और इसका उपयोग आसानी से होता है, इसलिए तरलता के अवरोही क्रम के अनुसार चार वर्गों में M_1, M_2, M_3 और M_4 के रूप में बांटा जा सकता है, जैसे कि M_1 मुद्रा का सबसे ज्यादा तरल रूप है, यानी M_1 के अंतर्गत मुद्रा के आधार में मुद्रा के तीनों घटकों को शामिल किया गया है। किसी अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार M_1 है। इसमें जन साधारण लोगों के पास मुद्रा को शामिल किया गया है, जिसमें कागज के नोट और सिक्के पाए जाते हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार 'सी' पर टिका है। इसी प्रकार व्यापारिक, वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा राशियां और चालू खाते डी.डी. के अंतर्गत आते हैं, यानी डिमांड ड्राफ्ट। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य बैंकों द्वारा जमा कराई गई राशियां होती हैं। ये विभिन्न संस्थान हैं, जिनके द्वारा धन राशि जमा कराई जाती है। आईडीबीआई जैसी वित्तीय संस्थाएं, विदेशी केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि संस्थान। किसी अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्योंकि सबसे ज्यादा तरल होता है, इसलिए इसे संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। मुद्रा आपूर्ति के लिए M_2, M_3, और M_4 श्रेणियों का भी उपयोग किया जाता है। इसमें M_4 एक व्यापक संकल्पना है, इसलिए इसे व्यापक मुद्रा कहा जाता है क्योंकि मौद्रिक आधार M_1, M_2 और M_3 शामिल होते हैं। M_1 की अपेक्षा M_2 अधिक व्यापक संकल्पना होती है, क्योंकि इसमें M_1 की प्रतिनिधित्वता करने वाले सारे घटक मौजूद रहते हैं और साथ में डाकघरों में बचत जमा राशियां भी शामिल होती हैं। जबकि M_3 और M_4 और व्यापक संकल्पना है। M_3 में M_1 के प्रतिनिधि कारक और व्यापारिक तथा वाणिज्यिक बैंकों के पास सबसे ज्यादा निवृत जमा राशियां पाई जाती हैं, जो कि M_1 और M_2 की अपेक्षा व्यापक होती हैं। इसी प्रकार M_4 में M_3 के साथ-साथ डाकघरों के पास बचत राशियां भी शामिल की जाती हैं। M_4 सबसे अधिक व्यापक संकल्पना पर आधारित श्रेणी है। इसलिए इसे व्यापक मुद्रा भी कहा जाता है। इस प्रकार किसी अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार प्रत्येक प्रकार की जमा राशि है, उसका रूप किसी भी प्रकार का हो सकता है। नकद मुद्रा भी और जमा मुद्रा भी जो कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बैंक में जमा कराई जाती है। यहां M_1 एक आरक्षित मुद्रा है।

प्रश्न 3. जमा गुणक क्या होता है? इसका नकद आरक्षित अनुपात से क्या संबंध है?

उत्तर–जमा गुणक यानी CD नकद जमा राशियों का गुणक होता है, जो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्धारित और निर्मित किया जाता है। यह उस साख को निर्धारित करता है। जमा गुणक सामान्य रूप में किसी भी बैंक में जमा की गई राशि का एक प्रतिशत होता है। मुद्रा की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए जमा गुणक की विशेष आवश्यकता होती है। आंशिक आरक्षित बैंकिंग प्रणाली लगभग जमा गुणक पर निर्भर रहती है। इसे मुख्य रूप से जमा विस्तार गुणक और साधारण जमा गुणक भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के समान ही केंद्रीय और अन्य बैंकों को न्यूनतम राशि रखने का अधिकार होना चाहिए। इसे आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। जमा गुणक किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि बैंकों द्वारा साख मुद्रा के रूप में निर्मित मुद्रा। जमा गुणक बैंकों द्वारा लोगों को दिया जाने वाला वह ऋण होता है, जो कि नकद आरक्षित अनुपात और लोगों द्वारा बैंकों में जमा की गई नकद और माँग जमा राशियों पर मिलने वाली मुद्रा है। CD यानी जमा गुणक और नकद आरक्षित अनुपात का आपस में विलोम संबंध है। यानी नकद आरक्षित अनुपात का स्तर जितना अधिक होगा, जमा गुणक का प्रतिशत

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com